



2026:AHC:65930

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

धारा 528 के तहत आवेदन संख्या- 12653 वर्ष 2026

विशाल पाठक आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: लक्ष्मी नारायण मिश्रा

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 74

माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक वर्मा

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री एचके चतुर्वेदी और श्री लक्ष्मी नारायण मिश्रा को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. आवेदक द्वारा धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत प्रस्तुत आवेदन दायर किया गया है, जिसमें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या-5, मेरठ द्वारा धारा 138 एन.आई. अधिनियम, थाना-सिविल लाइंस, जिला- मेरठ के तहत शिकायत मामले संख्या-11176 वर्ष 2025 (महीप सिंह बनाम विशाल पाठक) में पारित संज्ञान और समन आदेश दिनांक 16.10.2025 के साथ पूरी कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने दिनांक 16.10.2025 के समन आदेश और प्रतिपक्षी संख्या- द्वारा धारा 138 एन.आई. अधिनियम के तहत दर्ज की गई शिकायत को दो आधारों पर चुनौती दी है। पहला आधार यह है कि बी.एन.एस.एस. की धारा 223(1) को देखते हुए, आवेदक को संज्ञान लेने से पहले सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था, जैसा कि कथित तौर पर उक्त प्रावधान के तहत अनिवार्य है और दूसरा तर्क यह है कि आवेदक ने आरटीजीएस के माध्यम से सभी राशि का भुगतान कर दिया है और पक्षों के बीच कोई विवाद लंबित नहीं है, इसलिए कार्यवाही को रद्द कर दिया जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक के अधिवक्ता द्वारा की गई दलील का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि आवेदक के अधिवक्ता का पहला तर्क यह है कि आवेदक को बी.एन.एस.एस. की धारा 223(1) के तहत प्रावधान में अवसर नहीं दिया गया था, संजाबिज तारी बनाम किशोर एस. बोरकर के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को देखते हुए स्वीकार्य नहीं है और 25.09.2025 को आपराधिक अपील संख्या-1755 वर्ष 2010 में एक अन्य रिपोर्ट में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तर-ई में माना है कि: -

"ई- हाल ही में, **अशोक बनाम फैयाज अहमद, 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन 490** में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह विचार लिया है कि चूंकि एन.आई. अधिनियम एक विशेष अधिनियम है, इसलिए एन.आई.अधिनियम की धारा 138 के तहत दायर शिकायतों का संज्ञान लेने से पहले (बी.एन.एस.एस. की धारा 223 के तहत) अभियुक्त को समन जारी करने की मजिस्ट्रेट की कोई आवश्यकता नहीं है। यह न्यायालय कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत है। नतीजतन, यह न्यायालय निर्देश देता है कि बी.एन.एस.एस. की धारा 223 के संदर्भ में आरोपी को समन जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, यानी पूर्व-संज्ञान चरण में।

5. धारा 138 एन.आई. अधिनियम के तहत कार्यवाही एक समन कार्यवाही है और धारा 223(1) बी.एन.एस.एस. के तहत प्रावधान लागू नहीं हो सकता है, इसलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उठाया गया पहला आधार स्वीकार्य नहीं है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उठाया गया दूसरा आधार विवादित तथ्य का प्रश्न है क्योंकि उसने आरटीजीएस के माध्यम से प्रतिपक्षी संख्या-2 को किए गए भुगतान के संबंध में दस्तावेजों को संलग्न किया है और अनुलग्नक संख्या-3 खाते के विवरण का खुलासा करता है।

6. पक्षों के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्कों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने पाया कि आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उठाया गया दूसरा निवेदन तथ्य का विवादित प्रश्न है जिसकी धारा 528 बी.एन.एस.एस. के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय इस



स्तर पर जांच नहीं की जा सकती है। इसके मद्देनजर, आवेदक के अधिवक्ता द्वारा उठाए गए तर्क तर्कसंगत और स्वीकार्य हैं।

7. श्री ओम सेल्स बनाम अभय कुमार @ अभय पटेल और 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 2897 में रिपोर्ट किए गए अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णयों पर विचार किया है:

"14. मारुति उद्योग लिमिटेड बनाम नरेंद्र और अन्य में, इस न्यायालय ने माना कि एक अनुमान लगाया जाना चाहिए कि चेक के धारक को किसी भी ऋण या अन्य दायित्व के निर्वहन के लिए धारा 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चेक प्राप्त हुआ है, जब तक कि तत्स्य विपरीत साबित न हो जाए और इसलिए, उच्च न्यायालय कार्यवाही के प्रारंभिक चरण में अभियुक्त की याचिका पर विचार करने और उसे स्वीकार करने और शिकायत को रद्द करने में उचित नहीं था।

15. इसी तरह, रंगप्पा बनाम श्री मोहन में, यह माना गया था कि एन.आई. अधिनियम की धारा 139 द्वारा अनिवार्य अनुमान में कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण या देयता का अस्तित्व शामिल है। यह देखा गया कि इस तरह की धारणा खंडन योग्य है, और अभियुक्त को मुकदमे में अपना बचाव करना चाहिए।

16. राजेशभाई मुलजीभाई पटेल बनाम गुजरात राज्य में, यह माना गया था कि उच्च न्यायालय को ऋण या देयता के निर्वहन के लिए जारी किए जा रहे चेक के संबंध में तथ्य के विवादित प्रश्नों में जाकर एन.आई. अधिनियम की धारा 138 के तहत आपराधिक शिकायत को रद्द नहीं करना चाहिए। इसके अलावा, जब एन.आई. अधिनियम की धारा 139 ऋण या देयता के निर्वहन के लिए जारी किए जा रहे चेक के संबंध में एक वैधानिक धारणा उठाती है।

8. रतीश बाबू उन्नीकृष्णन बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) में, इस न्यायालय ने माना कि जब एन.आई. अधिनियम की धारा 139 के तहत कोई कानूनी धारणा होती है, तो शिकायत को रद्द करने के लिए पूर्व-परीक्षण चरण में तथ्य के



विवादित प्रश्न पर विस्तृत जांच करना विवेकपूर्ण नहीं होगा। निर्णय में प्रासंगिक टिप्पणियां नीचे दी गई हैं:

"17. जैसा कि ऊपर निर्धारित कानून का प्रस्ताव यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट करता है कि अदालत को पूर्व-परीक्षण चरण में शिकायत को रद्द करने की राहत देने में धीमा होना चाहिए, जब तथ्यात्मक विवाद विशेष रूप से कानूनी अनुमान के कारण संभावना के दायरे में हो, जैसा कि इस मामले में है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि किसी भी सबूत को जोड़ने के बिना तथ्यात्मक बचाव को एक अभेद्य गुणवत्ता की आवश्यकता है, ताकि शिकायत में लगाए गए आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया जा सके।

18. पूर्व-परीक्षण चरण में आपराधिक प्रक्रिया को बाधित करने के परिणाम गंभीर और अपूरणीय हो सकते हैं। प्रारंभिक चरणों में कार्यवाही को रद्द करने के परिणामस्वरूप पक्षों को सबूत पेश करने का अवसर नहीं मिलेगा और इसका परिणाम यह होगा कि उचित मंच यानी विचारण न्यायालय को भौतिक साक्ष्य का वजन करने से बाहर कर दिया जाता है। यदि इसकी अनुमति दी जाती है, तो अभियुक्त को आपराधिक प्रक्रिया में अनुचित लाभ दिया जा सकता है। इसके अलावा, कानूनी अनुमान के कारण, जब अपीलकर्ता द्वारा चेक और हस्ताक्षर पर विवाद नहीं किया जाता है, तो इस स्तर पर सुविधा का संतुलन शिकायतकर्ता/अभियोजन पक्ष के पक्ष में होता है, क्योंकि अभियुक्त को अनुमान का खंडन करने के लिए मुकदमे के दौरान बचाव पक्ष में साक्ष्य पेश करने का अवसर मिलेगा।

19. इस प्रकार, शिकायतकर्ता को गैर-सूट करने के लिए, सम्मन आदेश के चरण में, जब तथ्यात्मक विवाद को अभी तक प्रचारित नहीं किया गया है और विचारण न्यायालय द्वारा विचार किया जाना है, हमारी राय में विवेकपूर्ण नहीं होगा। प्रथम दृष्टया धारणा के आधार पर, विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारण के अधीन यहां आपराधिकता के एक तत्व को पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। इसलिए, जब कार्यवाही एक प्रारंभिक चरण में होती है, तो आपराधिक प्रक्रिया को रद्द करने के योग्य नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त मामले का निर्णय करते समय, प्रस्तर-13 और 18 में कहा है कि:

"13. हालांकि, उच्च न्यायालय ने धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में, यह परीक्षण करने के लिए आगे बढ़े कि क्या चेक किसी भी ऋण या अन्य देयता के पूरे या आंशिक रूप से निर्वहन के लिए जारी किया गया था। हमारे विचार में, इस तरह की कवायद अनुचित थी क्योंकि, एन.आई. अधिनियम की धारा 139 के तहत, एक धारणा है कि चेक के धारक को किसी भी ऋण या अन्य देयता के निर्वहन के लिए, पूरी तरह या आंशिक रूप से, धारा 138 में निर्दिष्ट प्रकृति का चेक प्राप्त हुआ था। इस अनुमान का खंडन मुकदमे में किए गए सबूतों द्वारा किया जा सकता है। एक फोर्टियोरी, उक्त मुद्दे को उचित रूप से या तो मुकदमे में, या बाद में, मुकदमे के समापन पर, अपीलीय/पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा तय किया जा सकता है।

"18. इस न्यायालय के पूर्वोक्त निर्णयों के साथ-साथ एन.आई. अधिनियम की धारा 139 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने ऋण या देयता के निर्वहन के लिए जारी किए जा रहे चेक के संबंध में, पूर्व-परीक्षण चरण में एक रोविंग जांच करके एक त्रुटि की है। हमारे विचार में, इस तरह की कवायद संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करने के योग्य नहीं थी, खासकर जब शिकायत के आरोपों से पता चला कि चेक दायित्व के निर्वहन के लिए जारी किया गया था। चूंकि धारा 138 एन.आई. अधिनियम के आवश्यक अवयवों की पूर्ति प्रथम दृष्टया शिकायत के आरोपों से बनाई गई है, इसलिए हमारे विचार में, न तो समन आदेश और न ही शिकायत को उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व-परीक्षण चरण में रद्द किया जा सकता था।

10. सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, प्रस्तुत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

मार्च 30, 2026

निशा



(न्यायमूर्ति दीपक वर्मा)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा!